UNIVERSITY NEWS 02 APRIL 2026

DAINIK JAGRAN

अब सेल्फ फाइनेंस शिक्षक भी परामर्श सेवाओं में होंगे शामिल

लखनऊ विश्वविद्यालय ने परामर्श नीति-2026 को दी स्वीकृति

जासं • लखनऊ : अब नियमित के साथ-साथ स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक भी परामर्श सेवाओं में शामिल हो सकेंगे। साथ ही पीएच.डी धारक तकनीकी कर्मचारी भी सह अन्वेषक के रूप में परामर्श कार्य कर सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2020 की पुरानी परामर्श नीति की जगह 2026 नीति को मंजूरी देते हुए कई बदलाव किए हैं। हाल ही में हुई विद्या परिषद की बैठक में इसे स्वीकृति मिल गई। इस नीति को पहले की तुलना में अधिक समावेशी, विस्तृत और पेशेवर बनाया गया है।

निदेशक परामर्श रितु नारंग ने बताया कि परामर्श नीति के संचालन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसमें कुलपति (अध्यक्ष), निदेशक परामर्श, सभी संकायों के अधिष्ठाता, वित्त अधिकारी और कुलसचिव शामिल होंगे। यह नीति न केवल विश्वविद्यालय के लिए राजस्व के नए स्रोत पैदा करेगी, बल्कि छात्रों और शोधकर्ताओं को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी देगी।

दूजी और शोध छात्रों को 100 रुपये प्रति घंटा : स्नातक और शोध छात्रों को प्रोजेक्ट में शामिल करने पर 100 रुपये प्रति घंटा (अधिकतम 50 घंटे प्रतिमाह) का भुगतान किया जाएगा। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संकायों में परीक्षण कार्यों पर प्रोजेक्ट का खर्च निकालने के बाद विश्वविद्यालय का हिस्सा 40 प्रतिशत और शिक्षकों का हिस्सा 60 प्रतिशत होगा। कला एवं अन्य संकायों में विश्वविद्यालय का हिस्सा 30 प्रतिशत और शिक्षकों का हिस्सा 70 प्रतिशत होगा। नीति के तहत तकनीकी सलाह, व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन, आडिट, और विशेष मामलों में मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट जैसे व्यक्तिगत परामर्श भी दिए जा सकेंगे।

राजनीति विज्ञान में एक सीट पर 31 दावेदार

जागरण संवाददाता • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएच.डी के कई ऐसे विषय हैं जिनमें प्रवेश के लिए कड़ा मुकाबला है। एक सीट पर कई गुणा अभ्यर्थियों की दावेदारी है। लवि की ओर से जारी विवरण के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय में प्रवेश के लिए सबसे ज्यादा मांग है। इस विषय में 19 सीटों के सापेक्ष 592 अभ्यर्थी हैं। यानी एक सीट पर 31 की दावेदारी है। पत्रकारिता एवं जन संचार विषय में सिर्फ दो सीटों पर 32 अभ्यर्थी यानी प्रति सीट 16 अभ्यर्थी हैं। इसी तरह गृह विज्ञान और भूगोल में एक-एक सीट पर 14 तो प्रबंधन अध्ययन विषय में प्रति सीट 15 अभ्यर्थी मैदान में हैं। कामर्स भी पीछे नहीं है। यहां प्रति सीट 12 अभ्यर्थी प्रवेश की लाइन में हैं। अंग्रेजी में 44 सीटों पर 327 अभ्यर्थी हैं। ऐसे में इस पर प्रति सीट सात लोगों की दावेदारी है। वहीं,हिंदी में 103 सीटों पर 630 अभ्यर्थी हैं। इसमें प्रति सीट छह दावेदार हैं। जल्द ही पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिखित परिणाम जारी होंगे।

विषय	सीटें	अभ्यर्थी
मनोविज्ञान	13	115
प्राणीशास्त्र	52	229
भूगोल	6	82
शिक्षा शास्त्र	44	335
विधि	70	451
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	23	190
अर्थशास्त्र	38	163
गणित	18	92
बायोकेमिस्ट्री	12	56
पश्चिमी इतिहास	11	29
प्रबंधन अध्ययन	6	90
होम साइंस	7	99

"यह नई परामर्श नीति लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए एकेडेमिया-इंडस्ट्री इंटरफेस' को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमने एक ऐसा पारदर्शी ढांचा तैयार किया है जहां शिक्षक अपनी विशेषज्ञता का उपयोग समाज और उद्योग की समस्याओं को सुलझाने में कर सकेंगे। इससे न केवल विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधन जुटेंगे, बल्कि हमारे छात्रों को भी व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा। -प्रो. जेपी सैनी, कुलपति, लवि

AMRIT VICHAR

सम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि 13 अप्रैल

अमृत विचार, लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टर जून 2026 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के नियमित, बैक पेपर, इम्प्रूवमेंट एवं एक्जेम्प्टेड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को छोड़कर अन्य सभी पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नियमित छात्रों को केवल ऑनलाइन फॉर्म भरकर उसकी प्रति सेमेस्टर शुल्क रसीद के साथ अपने विभागाध्यक्ष या संकायाध्यक्ष कार्यालय में जमा करनी होगी। वहीं बैक पेपर, इम्प्रूवमेंट एवं एक्जेम्प्टेड श्रेणी के छात्रों को परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करते हुए फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी फॉर्म ऑनलाइन अग्रसारित कर उनकी सूची 16 अप्रैल तक परीक्षा विभाग में अनिवार्य रूप से जमा कराएं। सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों को भी अपने-अपने कॉलेज में फॉर्म जमा करना होगा, जिसे कॉलेज लॉगिन के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

आवेदन में परेशानी आए तो करें संपर्क

फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि या समस्या होने पर छात्र हेल्पलाइन नंबर 7897999211, 7897992064, व्हाट्सएप 7897992062, लैंडलाइन 0522-4150500 या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।

AMAR UJALA

लविवि: छह पाठ्यक्रमों के नतीजे जारी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा के तहत बुधवार को परास्नातक के छह पाठ्यक्रमों का परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि एमए दर्शनशास्त्र, कंपोजिट हिस्ट्री व वेस्टर्न हिस्ट्री के प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ है। एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एमएससी जैव रसायन और एमएससी पर्यावरणीय विज्ञान पाठ्यक्रम के भी प्रथम सेमेस्टर का नतीजा विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। (माई सिटी रिपोर्टर)

AMAR UJALA

प्रोत्साहन | लखनऊ विश्वविद्यालय की कंसल्टेंसी पॉलिसी 2026 लागू

विकास में नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभाएगा लविवि

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। शैक्षणिक और शोध गतिविधियों को नई दिशा देते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कंसल्टेंसी पॉलिसी 2026 को लागू कर दिया है। विद्या परिषद ने 28 मार्च को इसे मंजूरी दी, जिसके साथ ही वर्ष 2020 की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई।

नई नीति के तहत इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विज्ञान, कृषि, योग, कला, वाणिज्य, विधि, ललित कला, शिक्षा और अभिनवगुप्त संकाय सहित सभी विभागों के शिक्षकों को परामर्श कार्यों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे लविवि प्रदेश के विकास में नॉलेज पार्टनर की भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेगा। अब शिक्षकों की विशेषज्ञता उद्योगों, सरकारी संस्थाओं और बाहरी निकायों तक पहुंचेगी, जिससे विश्वविद्यालय को अतिरिक्त आय के स्रोत मिलेंगे।

अब उद्योगों, सरकारी संस्थाओं और बाहरी निकायों तक पहुंचेगी शिक्षकों की विशेषज्ञता

नीति के अनुसार नियमित और स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक कंसल्टेंसी में शामिल हो सकेंगे। पीएचडी धारक तकनीकी कर्मचारी सह-अन्वेषक के रूप में सहयोग करेंगे। संचालन के लिए कुलपति की अध्यक्षता में कंसल्टेंसी प्रबंधन समिति बनाई गई है। राजस्व साझाकरण में विज्ञान व इंजीनियरिंग संकायों में 60 प्रतिशत हिस्सा शिक्षकों और 40 फीसदी विश्वविद्यालय को मिलेगा। अन्य संकायों में शिक्षकों को 70 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने इसे अहम कदम बताया।

NBT

विवि की ओर से कंसल्टेंसी पॉलिसी को दी गई मंजूरी, आय का बड़ा हिस्सा शिक्षकों को मिलेगा

निजी कंपनियों के लिए भी काम कर सकेंगे LU के टीचर

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ:** लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) के शिक्षकों के लिए अब अपनी विशेषज्ञता का लाभ निजी कंपनियों को देने का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई 'कंसल्टेंसी पॉलिसी' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शिक्षक निजी कंपनियों, सरकारी प्रॉजेक्ट्स और अन्य संस्थानों के लिए तकनीकी सलाह और परामर्श (कंसल्टेंसी) दे सकेंगे। विवि की कंसल्टेंसी निदेशक डॉ. रितु नारंग ने बताया कि इस नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे शिक्षकों की जेब में जाएगा, जबकि छात्रों को भी इस काम में शामिल होने पर प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। कंसल्टेंसी से होने वाली आय को विवि और शिक्षकों के बीच एक निश्चित अनुपात में बांटा जाएगा।

ऐसे होगा बंटवारा

- कला और अन्य संकाय : शिक्षकों को 70%, विवि को 30%
- विज्ञान और इंजिनियरिंग संकाय : विवि को 40%, शिक्षकों को 60%
- किसी कंसल्टेंसी प्रॉजेक्ट में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो उन्हें 100 रुपये प्रति घंटा की दर से भुगतान किया जाएगा।
- कोई भी छात्र एक महीने में अधिकतम 50 घंटे तक इस तरह के काम में भाग ले सकेगा

ये सेवाएं दे सकेंगे शिक्षक

इस पॉलिसी का दायरा काफी व्यापक रखा गया है। शिक्षक न केवल तकनीकी सलाह दे सकेंगे, बल्कि सर्वे, डिजाइनिंग, ऑडिट और डेटा विश्लेषण जैसे काम भी कर सकेंगे।

अब शिक्षक अपनी विशेषज्ञता का उपयोग समाज और उद्योगों की समस्याओं को सुलझाने में भी कर सकेंगे। इससे विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधन भी जुटाए जा सकेंगे।

– प्रो. जेपी सैनी, कुलपति, LU

विदेशी छात्रों को बिना शर्त दाखिला

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ:** लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विदेशी छात्र अब फोर इयर ग्रैजुएशन में बिना शर्त दाखिला मिल सकेगा। विवि की ओर से नियम बनाया गया था कि थ्री इयर के बाद फोर इयर ग्रैजुएशन में उन्हें ही दाखिला दिया जाएगा कि जिनके 7.5 सीजीपीए से अधिक अंक है। इससे कम वाले छात्रों को थ्री इयर ग्रैजुएशन की डिग्री लेकर कोर्स पूरा करना पड़ रहा है।

एलयू ने 4 ईयर ग्रेजुएशन में खत्म की सीजीपीए की बाध्यता

इस पर कई विदेशी छात्रों ने मांग की थी कि उनके लिए यह बाध्यता खत्म की जाए। इंटरनैशनल स्टूडेंट एडवाइजर डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि पिछले साल से 7.5 सीजीपीए का नियम लागू किया गया था। कई विदेशी छात्रों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उनके देशों में फोर इयर ग्रैजुएशन पर ही प्रैक्टिस की अनुमति है। इसी को लेकर छात्रों ने विवि प्रशासन को पत्र लिखा था।

कॉलेज तय करेंगे इंजिनियरिंग का सिलेबस

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ:** डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) से संबद्ध इंजिनियरिंग कॉलेज अब खुद ही तय करेंगे कि वह सिलेबस में क्या पढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय ने बीटेक प्रथम वर्ष के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी की है। विवि ने इस बार सिलेबस कॉलेजों पर थोपने के बजाय कॉलेजों को ही यह मौका दिया है कि वे अपनी जरूरतों और बाजार की मांग के हिसाब से सिलेबस तय करें। इसके लिए एकेटीयू की ओर से सभी कॉलेजों को पत्र जारी किया गया है। स्किल डिवेलपमेंट और 'एआई' जैसे उभरते क्षेत्रों को कितना और किस स्तर पर शामिल किया जाए, इसमें भी कॉलेजों का इनपुट मांगा गया है। कॉलेजों को 15 दिनों के भीतर अपने सुझाव ईमेल के जरिए भेजने होंगे।

एकेटीयू की ओर से सभी कॉलेजों को जारी किया गया पत्र

मार्कशीट में ऑनलाइन कोर्स भी होंगे दर्ज

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ:** बीबीएयू में अब छात्र ऑनलाइन कोर्स कर डिग्री में स्पेशलाइजेशन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अन्य डिग्री या स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विवि ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन कोर्स को भी मार्कशीट में जोड़ जाएगा। इससे अब सिविल से बीटेक करने वाले छात्रों को अगर एआई में स्पेशलाइजेशन करना है तो उन्हें दूसरे कोर्स में ऐडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एआई पर ऑनलाइन कोर्स करके वह मार्कशीट में उसका स्पेशलाइजेशन जुड़वा सकेंगे।

AMAR UJALA

एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर बेहतर होगा लाइब्रेरी सिस्टम

लखनऊ। डिजिटल और एआई आधारित वर्गीकरण तकनीक से पुस्तकालयों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी व सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की शोधार्थी डॉ. कृतिका अग्रवाल और डॉ. बबीता जायसवाल ने सात दशकों में प्रकाशित 296 शोध-पत्रों के विश्लेषण पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसमें लाइब्रेरी वर्गीकरण के विकास, बदलते रुझानों और भविष्य की दिशा को स्पष्ट किया गया है।

लाइब्रेरी वर्गीकरण पर सात दशकों के रुझान का लविवि में अध्ययन

अध्ययन में सामने आया कि 1960 का दशक 'वर्गीकरण शोध' का स्वर्णकाल रहा, खासकर 1969 से 1973 के बीच। इस दौरान प्रख्यात पुस्तकालय वैज्ञानिक डॉ. एसआर. रंगनाथन के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है।

वर्ष 1972 के बाद शोध गतिविधियों में गिरावट आई, लेकिन 2004 से 2013 के बीच इसमें कुछ सुधार दर्ज किया गया। प्रमुख योगदानकर्ताओं में डॉ. एसआर. रंगनाथन, ए. नीलामेघन और एम. ए. गोपीनाथ जैसे विद्वानों के नाम हैं। संस्थागत स्तर पर बंगलूरू स्थित डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का योगदान सबसे अधिक रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य संस्थानों की भी अहम भूमिका रही। (माई सिटी रिपोर्टर)

AMRIT VICHAR

दुनिया में 1972 के बाद घटी शोध की प्रवृत्ति

अमृत विचार, लखनऊ : दुनिया भर में सर्वाधिक शोध कार्य 1972 से पहले हुए, इसके बाद शोध की प्रवृत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। यह निष्कर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की शोधार्थी डॉ. कृतिका अग्रवाल और डॉ. बबीता जायसवाल द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है। अध्ययन एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन स्टडीज (1954-2024) और जर्नल ऑफ इंफार्मेशन एंड नॉलेज (1964-2024) में प्रकाशित वर्गीकरण संबंधी शोधों पर आधारित है। सात दशकों में प्रकाशित 296 शोध पत्रों के विश्लेषण से लाइब्रेरी वर्गीकरण के विकास, प्रवृत्तियों और भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया गया। शोध के अनुसार 1960 का दशक इसका स्वर्णकाल रहा, खासकर 1969 से 1973 के बीच विश्वभर में सबसे अधिक शोध हुए। यह दौर प्रख्यात पुस्तकालय वैज्ञानिक डॉ. एस. आर. रंगनाथन के योगदान से प्रभावित था। अध्ययन में बताया गया कि 1972 के बाद शोध कार्यों में गिरावट आई।